नईदुनिया

डोनाल्ड ट्रंप के बदलावों से अमेरिकी जीवन का हर पहलू प्रभावित

वाशिंगटन

व्हाइट हाउस में दूसरे कार्यकाल के लिए इस साल जनवरी में धमाकेदार एंट्री करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के बदलाव से अमेरिकी जीवन का हर पहलू प्रभावित हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ने अपनी आक्रामक नीति और ध्रुवीकरण में अपने सभी पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने ऐसे बदलावों की झड़ी लगा दी है, जिन्होंने अमेरिकी जीवन के शायद ही किसी पहलू को अछूता छोड़ा है। अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब तक की संक्षिप्त अवधि का विश्लेषण किया है। अखबार कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का उपयोग कच्ची राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने और देश को अपनी छवि में बदलने के इरादे से कार्यालय में वापसी की। चार महीने हो चुके हैं और उन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया है। राष्ट्र ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ट्रंप के बदलावों का असर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीयता, शिक्षा और सरकार पर पड़ा है। उनके इन कदमों ने उनके सहयोगियों और कट्टर आलोचकों को समान रूप से आश्चर्यचकित किया। यह अव्यवस्थित है और अकसर इसका अनुसरण करना काफी मुश्किल है। ऐसा लगता है यह सब जानबूझकर किया गया है। मानना है कि चाहे आप राष्ट्रपति के कार्यों से प्रसन्न हों या अचंभित, उनके पहले 100 दिनों का सदमा शायद अब कम हो रहा है।

साम्राज्यवाद के साथ खिलवाड़ – ट्रंप ने वैश्विक व्यवस्था और अमेरिका के गठबंधनों को उलट दिया है। राष्ट्रपति ने खुले तौर पर साम्राज्यवाद के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने देश को कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर हासिल करने का सुझाव दिया है। लेकिन विदेश नीति पर उनका प्रभाव इससे कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने पूरी तरह से सत्ता पर आधारित विदेश नीति अपनाई है। रूस और चीन जैसे देशों के साथ मजबूत व्यवहार के पक्ष में लंबे समय से सहयोगी रहे देशों को किनारे कर दिया है। उनके लिए अब यूरोप और इजराइल जैसे करीबी सहयोगी महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कानून की सीमा – वह कानून की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन ने बार-बार अदालती आदेशों का विरोध किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि सरकार गलत तरीके से निर्वासित व्यक्ति को वापस लाने के लिए कदम उठाए। ट्रंप ने उन न्यायाधीशों पर हमला किया है जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस द्वारा बहुत कम निगरानी की पेशकश और उनकी शक्ति पर अपने संवैधानिक नियंत्रण को लागू करने से परहेज करने के कारण, कुछ कानूनी विद्वान पहले से ही संवैधानिक संकट की चेतावनी दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि प्रशासन शक्तियों के पृथक्करण के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का परीक्षण कर रहा है।

निरंकुशता का अलार्म – वह समाज में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। कानूनी फर्में। विश्वविद्यालय। वैज्ञानिक अनुसंधान। मीडिया कंपनियां। विविधता, समानता और समावेश की नीतियां।

न्यूज ब्रीफ

अब यूक्रेन और रूस के बीच होगी सीधी वार्ता, तुर्किये, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में से एक जगह होगी बैठक

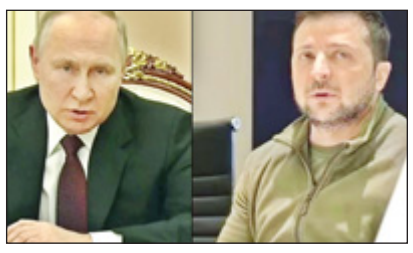

वाशिंगटन/मॉस्को/कीव। वर्षों से युद्ध में उलझे रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम कराने के वैश्विक प्रयास कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल चली दो घंटे की टेलीफोनिक बातचीत काफी हद तक सफल रही। पुतिन को ट्रंप काफी हद तक समझाने में सफल रहे। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बातचीत शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक ट्रंप के संपर्क में रहे। जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध विराम पर अगले दौर की वार्ता तुर्किये, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में से किसी एक स्थान पर हो सकती है। खबर के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उन्होंने व्यापक रियायतों की अपनी मांग दोहराई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि दो घंटे तक चली कॉल बहुत अच्छी रही। अब रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध समाप्त करने की दिशा में बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से वार्ता के बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं से भी बात की है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिन की शुरुआत में पुतिन की स्थिति पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन के पास युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई रणनीति है। खबर के अनुसार, पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बातचीत के लिए सोची तट पर स्थित एक संगीत विद्यालय को चुना। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस से बातचीत की। पुतिन ने अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट किया कि वह हिंसा को समाप्त करने की अपनी अधिकतम मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। पुतिन ने भी ट्रंप से हुई बातचीत को सार्थक बताया।

यूएई और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह जानकारी यूएई के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। यह समझौता अबू धाबी में यूएई के रक्षा मामलों के राज्यमंत्री मोहम्मद बिन मुबारक फाधेल अल मजरूई और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के बीच हस्ताक्षरित हुआ। बयान के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों की सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं को एकरूप करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समझौते के तहत, दोनों देश एक चरणबद्ध ढांचे के तहत काम करेंगे, जिसका उद्देश्य संयुक्त तैयारी, इंटरऑपरेबिलिटी और नवाचार-आधारित सहयोग को बढ़ावा देना है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस अवसर पर एक नई पहल की घोषणा की, जिसमें यूएस डिफेंस इनोवेशन यूनिट और यूएई के तवाज़ुन काउंसिल के बीच साझेदारी की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा नवाचार, संयुक्त अनुसंधान और विकास और उद्योग एवं निवेश क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी आज बन रही है सच्चाई

वाशिंगटन। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार पुनः चर्चा में है। भविष्यवाणी में उन्होंने एक छोटे

उपकरण के जरिए मानवता को खतरे में पड़ने की बात कही थी। कहा जा रहा है कि यह भविष्यवाणी आज के स्मार्टफोन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्थिति पर भी असर डाल रहा है। बाबा वेंगा ने दशकों पहले भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक छोटा सा उपकरण आएगा, जो शुरू में लोगों के लिए सहायक होगा लेकिन धीरे-धीरे वही इंसान का दुश्मन बन जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यह उपकरण बच्चों के लिए खतरा बनेगा और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाएगा। तब यह बात एक कल्पना जैसी लगती थी, लेकिन आज के दौर में जब स्मार्टफोन हर हाथ में है, तब वेंगा की यह चेतावनी बेहद सटीक और प्रासंगिक लगती है। आज स्मार्टफोन ने जहां एक ओर जीवन को आसान बनाया है, वहीं इसके अत्यधिक उपयोग ने नई समस्याओं को जन्म दिया है।

अल साल्वाडोर में राष्ट्रपति बुकेले की आलोचक वकील लोपेज गिरफ्तार

सैन सैल्वाडोर

अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले की मुखर आलोचक और प्रमुख वकील रूथ एलोनोरा लोपेज को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति नायब बुकेले के इशारे पर की गई गिरफ्तारी की अधिकार समूहों ने तीखी आलोचना की है। समूहों का कहना है कि यह देश में अधिनायकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने लोपेज पर राज्य के खजाने से धन की चोरी में सहयोग करने का आरोप जड़ा है।

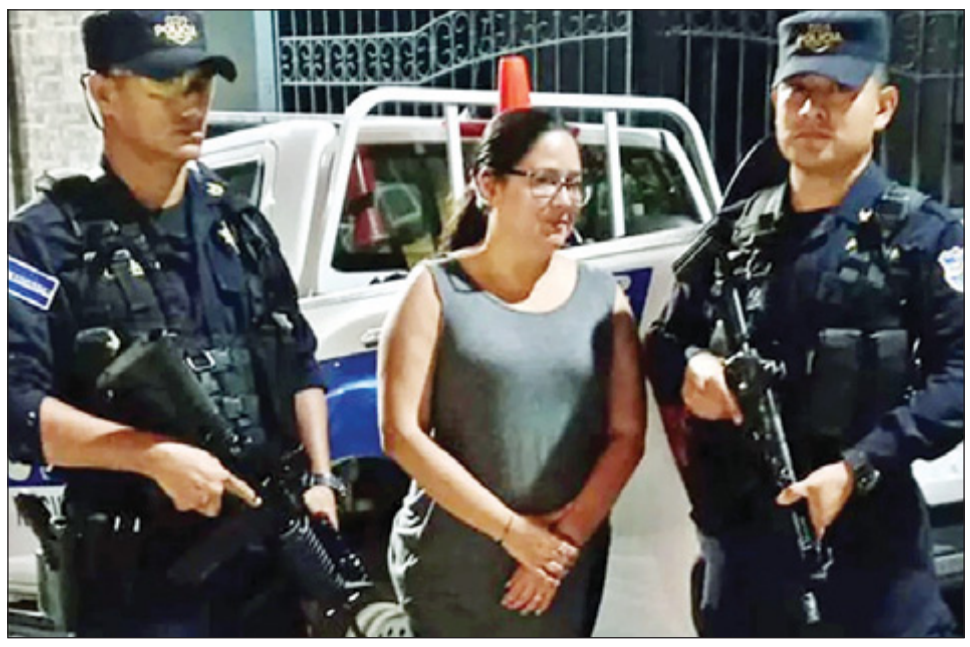

खबर के अनुसार, अल साल्वाडोर में अधिकारियों ने राष्ट्रपति नायब बुकेले की आलोचना करने वाली प्रमुख वकील रूथ एलोनोरा लोपेज गिरफ्तार किया है। अल साल्वाडोर के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने कहा कि अधिकार संगठन क्रिस्टोसल की भ्रष्टाचार विरोधी और न्याय इकाई की प्रमुख रूथ एलोनोरा लोपेज पर राज्य के खजाने से धन की चोरी में सहयोग करने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी छापेमारी के दौरान की गई जांच और एकत्रित जानकारी के आधार पर की गई। पीड़ित लोपेज की मां और उनके पति ने सोमवार को क्रिस्टोसल के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसे कहां रखा गया है कि यह तक नहीं बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उसके घर पर झूठे बहाने से आए और उसे बाहर निकालने के लिए एक यातायात दुर्घटना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और वारंट देखने की अनुमति तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वह अभी भी अटॉर्नी जनरल कार्यालय के एक्स पर पोस्ट किए गए औपचारिक आरोपों के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। क्रिस्टोसल में रणनीतिक मुकदमेबाजी के निदेशक अब्राहम एब्रेगो ने कहा कि इससे यह संदेश जाता है कि सरकार दमन करने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह तक नहीं बताया जा रहा कि वकील और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोपेज को कहां रखा गया है। लोपेज ने बुकेले सरकार की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है। अपराध पर नकेल कसने के लिए चल रही आपातकालीन स्थिति के दौरान दमन की निंदा की है। लोपेज को 2024 में बीबीसी ने 100 प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया था। वो 2009 और 2014 के बीच सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल के पूर्व अध्यक्ष यूजेनियो चिकास की सलाहकार थीं। चिकास को पिछले फरवरी में गिरफ्तार किए जाने के बाद मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद से बुकेले ने देश में वर्षों से व्याप्त अपराध और गिरोह हिंसा को रोकने के लिए विवादास्पद उपाय लागू किए हैं। 2022 में सांसदों के समर्थन से उन्होंने आपातकाल घोषित किया था। यह उपाय 30 दिन तक चलने वाला था, लेकिन इसे दर्जनों बार बढ़ाया गया और आज भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार, आपातकाल घोषित किए जाने के बाद से अब तक सुरक्षा बलों ने देश भर में लगभग 87,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित अंतरराष्ट्रीय समूहों ने सोमवार को संयुक्त बयान में लोपेज की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि अल साल्वाडोर में आपातकाल का इस्तेमाल न केवल गिरोह से संबंधित हिंसा को समाप्त करने के लिए किया गया है, बल्कि आलोचनात्मक आवाजों को चुप कराने के लिए भी किया गया है।

पोप से मिले जेडी वेंस, ट्रंप की ओर से अमेरिका आने का दिया निमंत्रण

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को वेटिकन में पोप लियो चौदहवें से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा का औपचारिक निमंत्रण सौंपा। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब अमेरिका की अगुवाई में रूस-यूक्रेन युद्ध में संघर्षविराम को लेकर कूटनीतिक प्रयासों की तेजी देखी जा रही है। जेडी वेंस ने शिकागो में जन्मे अमेरिका के पहले पोप को ट्रंप का पत्र सौंपा, जिसे पोप ने अपने डेस्क पर रखते हुए कहा, किसी समय ऐसा होगा। यह क्षण वेटिकन मीडिया द्वारा साझा की गई वीडियो फुटेज में रिकॉर्ड हुआ। कैथोलिक धर्म में वर्ष 2019 में धर्मांतरित हुए वेंस ने पोप को संत ऑगस्टीन की दो प्रसिद्ध रचनाएं- द सिटी ऑफ गॉड और ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन भी भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने एक खास उपहार शिकागो बियर्स की टी-शर्ट दी, जिस पर लिओ लिखा था। वेंस ने पोप से कहा, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, अमेरिका में लोग आपके बारे में बेहद उत्साहित हैं।

इजराइल ने सात दिन में हमास के 670 अधिक ठिकानों को बनाया निशाना

गाजा पट्टी

इजराइली सेना ने पिछले सात दिन में आतंकी समूह हमास के 670 से अधिक पर भीषण हमला किया है। पिछले 24 घंटों में इजराइल के हमलों में कम से कम 136 लोगों की जान चली गई। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने गाजा में खाद्य पदार्थों की बुनियादी मात्रा को प्रवेश करने की अनुमति दी है।

खबर के अनुसार, इजराइली सेना ने कहा कि पिछले हफ्ते उसने पूरे एन्क्लेव में प्रारंभिक हवाई हमलों में हमास के 670 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। यूके स्थित संगठन के अनुसार, सोमवार सुबह इजराइली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल सप्लाई गोदाम पर हमला किया।

गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में इजराइल के हमलों में कम से कम 136 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार से सोमवार तक 400 से अधिक लोग मारे गए और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए। सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल के युद्ध शुरू किए जाने के बाद से गाजा में 53,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को कहा कि गाजा में अकाल को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों की एक बुनियादी मात्रा को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। हालांकि इससे उसका सैन्य अभियान खतरे में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया है कि यदि इजराइल 11 सप्ताह की नाकाबंदी नहीं हटाता है तो इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अपने सबसे करीबी सहयोगियों का समर्थन खो सकता है।

यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल से गाजा में अपने सैन्य अभियानों को रोकने और मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति देने का आह्वान किया है। इन देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि अगर इजराइल ने आक्रमण बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर अपने प्रतिबंध नहीं हटाए तो जवाब में और ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसमें लक्षित प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जवाब में इन नेताओं पर सात अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकियों को इनाम देने और इनके अत्याचारों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उधर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके सहित 23 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने इजराइल से आग्रह किया कि वह गाजा में संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने में मदद करे।

बांग्लादेश की अभिनेत्री नुसरत फारिया के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, हत्या के प्रयास के केस में ढाका अदालत ने दी जमानत

ढाका

बांग्लादेश की मशहूर अभिनेत्री नुसरत फारिया के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने जेल जाने के 24 घंटे बाद ढाका की अदालत ने आज सुबह जमानत प्रदान कर दी। 31 वर्षीय फारिया को हत्या के प्रयास के एक केस में हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। फारिया के वकील मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि ढाका की एक अदालत ने आज सुबह अभिनेत्री को जुलाई विद्रोह से जुड़े हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत दे दी।

वकील हुसैन ने बताया कि ढाका के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। कल उन्हें इस मामले के सिलसिले में जेल भेज दिया गया। अदालत ने कल जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की थी, क्योंकि उनके वकील इफ्तिखार ने उनके यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत किए और कहा कि वह नौ जुलाई से 13 अगस्त के बीच कनाडा में थीं, जब ढाका के भटारा इलाके में अपराध हुआ था। अभिनेत्री की गिरफ्तारी की कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों, खासकर जुलाई के विद्रोह के दौरान मुखर रहे लोगों ने व्यापक आलोचना की थी। अभिनेत्री को कल सुबह करीब 10:00 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया गया, इससे एक दिन पहले उन्हें हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से पहले गिरफ्तार किया गया था। वह थाईलैंड जा रही थीं। पिछले साल 19 जुलाई को भटारा में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से घायल इनामुल हक ने इस साल 27 मार्च को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, 17 अभिनेता-अभिनेत्री और 265 अन्य के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। 29 अप्रैल को भटारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने अदालत के निर्देशानुसार इस पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

उल्लेखनीय है नुसरत फारिया का पूरा नाम नुसरत फारिया मजहर है। वह मॉडलिंग, गायन, टेलीविजन प्रस्तोता और रेडियो जॉकी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर नुसरत फारिया अकसर अपने लुक और पोस्ट की वजह से चर्चा में रहती हैं। दिलचस्प यह है कि नुसरत को 2023 की फिल्म मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भूमिका निभाने के बाद प्रसिद्धि मिली। यह फिल्म बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन पर आधारित थी।

मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन फिल्म भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त उद्यम थी और इसे दिवंगत दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया था।

नेपाल में वामपंथी दलों के बीच एकता कराने को चीन सक्रिय, पूर्व राष्ट्रपति को मिला बीजिंग दौरे का न्यौता

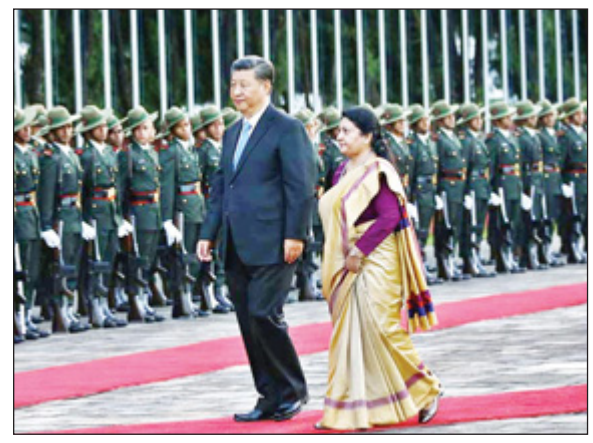

काठमांडू

नेपाल में एक बार फिर से प्रमुख वामपंथी दलों के बीच एकता की चर्चा और बहस शुरू हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रमुख विपक्षी नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड की पार्टी के बीच एकता कराने की मध्यस्थता के लिए चीन सक्रिय हो गया है।

इसी बीच बीजिंग ने देश की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को बीजिंग भ्रमण का न्यौता दिया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल से सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को 24 मई से एक सप्ताह के चीन भ्रमण पर बीजिंग का न्यौता मिला है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यूएमएल पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ बीजिंग जा रही विद्या भंडारी की वहां कई खास राजनीतिक मुलाकात होना तय है। चीन में नेपाल के राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने पूर्व राष्ट्रपति भंडारी के चीन भ्रमण की पुष्टि की है। काठमांडू आए राजदूत ओली ने बताया कि कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के अंतरराष्ट्रीय विभाग की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग दौरे के समय चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात तय है। चीन की पहल पर और पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी के प्रयास से पिछली बार हुई कम्युनिस्ट एकता को सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया था। बाद में ओली और प्रचंड की व्यक्तिगत टकराव की वजह से वह नहीं हो पाया। चीन एक बार फिर से नेपाल के प्रमुख वामपंथी दलों खास कर ओली और प्रचंड की पार्टी के बीच एकता कराने के लिए सक्रिय हो गया है। इसी वजह से ओली की पार्टी से सक्रिय राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को चीन बुलाकर एक बार फिर से दोनों प्रमुख वामपंथी दलों के बीच एकता कराने के अपने प्रयास में चीन ने भंडारी को बीजिंग बुलाया है।